(c) Does not arise.

Freight Service between Amritsar and Kabul

4406. SHRI ESWARA REDDY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether M/s. Jamair Co. (Private) Ltd., a private air company, was allowed to operate freight service between Amritsar and Kabul in 1961;

(b) whether there is any proposal under consideration to grant them similar facilities on other routes; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Jamair was allowed to operate non-scheduled flights between Amritsar and Kabul in 1961, on the basis of a 'no objection' certificate from Indian Airlines.

(b) There is no such proposal at present.

(c) Does not arise.

Allegations against West Bengal Police

4407. SHRI K. HALDER : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the serious allegations that the Police of West Bengal are helping Jotedars and employers against the peasants and workers; and

(b) if so, the steps Government propose to take to protect the peasants and workers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b). The State Government have reported that no specific instance has so far come to their notice.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह को स्वायत्तशासी इकाई का दर्जा दिये जाने की मांग

4408. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि अन्दमान तथा निकोबार दीप समूह की जनता उक्त दीप समूह को स्वायत्त शासी इकाई का दर्जा देने की बहुत समय से मांग कर रही है ;

(ख) क्या लोग मांग कर रहे हैं कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवा कर इस प्रयोजन के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). अंडमान और निकोबार द्वीप संघ शासित क्षेत्र में एक ऐसी प्रतिनिधि सरकार के लिए जो कि जनता के प्रति उत्तर-दायी हो तथा एक क्षेत्री परिषद की स्थापना के लिए मांगें की गई हैं ।